

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 93/XVIII(3)/2016-20(01)/2014—चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि.....
.....भूमि के अर्जन के कारण व्यक्तियों को गैर-स्वैच्छिक विस्थापन होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में पुनर्वासन अथवा पुनर्व्यवस्थापन के लिए (जो भी स्थिति हो अथवा दोनों के लिए)

श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 43(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सम्बन्धित जिले के अपर जिलाधिकारी (जनपद में अपर जिलाधिकारी का पद उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी) को उनके पद के अतिरिक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करने तथा उक्त धारा की उप धारा (2) में अवसंरचना आदि उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, उपधारा (3) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि एतद्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक समुचित सरकार और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और अनुश्रवण प्रशासक में निहित होगी।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 93/XVIII(III)/2016-20(01)/2014, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 93/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--WHEREAS the appropriate Government is satisfied that there is likely to be involuntary displacement of persons due to acquisition of land displacement for rehabilitation and resettlement (as the case may be),

NOW, THEREFORE, In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to appoint as a rehabilitation and resettlement administrator addition in his duties to the additional District Magistrate of concerning district (non-availability of the additional District Magistrate of the district the concerning SDM) and to provide office infrastructure etc. in the said sub-section (2).

2. The Governor is also pleased to direct under sub-section (3) that the hereby appointed administrator for rehabilitation and resettlement with subject to the superintendence, directions and control of the Commissioner for rehabilitation and resettlement and the formulation, execution and monitoring of the rehabilitation and resettlement scheme shall be vest in the administrator.

By Order,

D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 27-02-2016, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 राजस्व/144-14-03-2016-500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।